भारत बीमा निगम लिमिटेड का कोंकोर्ड

बनाम

निरमाला देवी और अन्य

16 अप्रैल, 1979

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और आर. एस. पाठक, जे. जे.]

वकील की लापरवाही जो एक वादी को उसके उपचार की देरी से खोज में गुमराह करती है- सीमा की गणना के मामले में कानूनी राय पर भरोसा करने वाली कंपनियों और अन्य व्यक्तियों की स्वामित्व और तर्कसंगतता - सीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम XXXVI) धारा 5

राज्य द्वारा बिना किसी दोष के यातनापूर्ण दायित्व की आवश्यकता-कानूनी अधिकार, वाहन, दुर्घटनाओं के मामले में साक्षरता और शिकायतों के निवारण को सुरक्षित करने वाले प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों को समझाया गया।

मोटर साइकिल पर सवार एक डॉक्टर और उसके भाई को नवंबर 1971 में एक जीप चालक ने टक्कर मार दी थी और दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने पांच साल बाद 5-9-1976 को दावेदारों के दो समूहों को 80, 000/- और 73,500/- रुपये का फैसला सुनाया।

इस मामले में अपील 19-1-77 पर या उससे पहले दायर की जानी थी, लेकिन वास्तव में 30 दिन बाद सीमा की अवधि की गणना में वकील की गलती के आधार पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफी के लिए एक आवेदन के साथ दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिका और आवेदन को खारिज कर दिया।

विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

एक कंपनी अपने कानूनी सलाहकार पर निर्भर करती है और प्रबंधक की विशेषज्ञता कंपनी प्रबंधन में होती है न कि कानून में। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि जब कोई कंपनी या अन्य व्यक्ति कानूनी मामलों पर उसे या उसे सलाह देने के लिए एक वकील रखता है तो ऐसे वकील पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बेशक, अगर आम आदमी के लिए भी पेटेंट में बहुत देरी होती है या अगर समझ में आने वाली उदासीनता है तो कानूनी राय की ढाल अभी भी कमजोर हो सकती है। यदि कानूनी सलाहकार की राय को कंपनी के प्रबंधकों द्वारा अपनी खुद की कानूनी जांच के अधीन किया जाना है, तो एक असंभव स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में सरकार, जो इस देश में एक बड़ी वादी है, खुद को कठिनाई में पा सकती है [697 ई-एफ, 698 एफ-जी]

यह अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में याचिकाकर्ता के लिए अपने आप वीजा सुरक्षित नहीं करता है। तथ्यात्मक निष्कर्षों में स्पष्ट अन्याय या घोर गलत सराहना या विकृति होनी चाहिए। [698 एच]

केरल राज्य बनाम कृष्ण कुरुप माधव कुरुप, ए. आई. आर. 1971 केरल 211; स्वीकृत।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हावड़ा नगर निगम, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 749; संदर्भित।

अभिनिर्धारितः 1. मोटर दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का न्यायशास्त्र बिना किसी दोष के दायित्व की दिशा में विकसित होना चाहिए और मात्रा का निर्धारण उदार होना

चाहिए, न कि मामूली रूप से क्योंकि कानून एक स्वतंत्र देश में जीवन और अंगों को उदार पैमाने पर महत्व देता है। सामाजिक न्याय, राज्य द्वारा स्वयं सड़क मरम्मत की उपेक्षा करके, घातक अधिभार को नजरअंदाज करके और बस परिवहन के बड़े हिस्से और पूरे सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के बाद दायित्व का विरोध करके संविधान के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। [696 सी-डी]

2. विश्वासघाती खतरों और पूरी तरह से जर्जर मध्ययुगीन सड़कें, भारी वाहनों की विस्फोटक वृद्धि अक्सर बहुत अधिक भार और बिना चेतावनी संकेतों के, लापरवाह चालक गति के साथ पागल और उत्तेजक औषधि के साथ टिपसी, सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए यातायात नियमों का गैर-प्रवर्तन लेकिन व्यवस्थित भ्रष्टाचार के अवसर प्रदान करते हैं और बहुत कम और, एक संचयी प्रभाव के रूप में, बढ़ती राजमार्ग दुर्घटनाएं, बिना किसी गलती के दायित्व और मुआवजे के दावों के मामलों में प्रक्रियात्मक गति और सरलता के माध्यम से अपकृत्य के कानून के लिए एक नए आयाम की मांग करती हैं। [696 बी-सी]

3. यदि केवल बिना किसी दोष के दायित्व, पुलिस द्वारा स्वचालित रिपोर्टिंग, जो दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित एक वैधानिक प्रो-फॉर्मा में दुर्घटना की जांच करती है और तमिलनाडु की तरह न्यायाधिकरण को भेजी जाती है और प्रत्येक जिले में ऐसे न्यायाधिकरणों के विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण के साथ अनौपचारिक प्रक्रियाएं और अदालत शुल्क से मुक्ति और सबूत के बोझ और सबूत के परिष्कृत नियम पेश किए गए थे-आसान और सस्ते, यदि राज्य में उन गरीबों की मदद करने की इच्छा है जो ज्यादातर इस तरह की दुर्घटनाओं में मर जाते हैं-इस अनुकंपा क्षेत्राधिकार में कानून की देरी को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक न्याय राज्य की संवैधानिक संवेदनशीलता का पैमाना है। [696F-G]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1977 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5228 और 5286।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1977 के एफ. ए. ओ. सं. 81 और 82 में दिनांक 8-8-1977 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता की ओर से पी. पी. मल्होत्रा और आर. एन. दीक्षित।

प्रतिवादी के लिए एस. के. गंभीर।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा दिया गया था-

कृष्णा अय्यर, जे.

ऑटोमोबाइल दुर्घटनाओं में एक विस्फोटक वृद्धि, जो सबसे घातक बीमारियों की तुलना में अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, हर जगह भारतीय सड़कों पर एक घातक घटना बन गई है। हमारी विधानसभाओं, अदालतों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर इस दुखद विकास का न्यायिक प्रभाव अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप गरीब, जो इनमें से अधिकांश मामलों में हताहत होते हैं, जीवन या अंगों के नुकसान का सामना करते हैं और उचित मात्रा में मुआवजे के रूप में त्वरित कानूनी उपचार से वंचित होते हैं-और यह अनिवार्य मोटर बीमा और बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद भी होता है। इन विशेष अनुमति याचिकाओं के तथ्य; जिसे हम इस आदेश द्वारा खारिज करते हैं, दो गंभीर मुद्दे उठाते हैं जो हमें बोलने का आदेश देने के लिए विवश करते हैं। पहला कानूनी अधिकारों, वाहन दुर्घटनाओं के मामले में साक्षरता और शिकायतों के निवारण को सुरक्षित करने वाले प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों से संबंधित है। दूसरा वकील की लापरवाही के परिणामों से संबंधित है जो एक वादी को अपने उपचार की देरी से खोज में गुमराह करता है।

विश्वासघाती खतरों और पूरी तरह से जर्जर मध्ययुगीन सड़कें, भारी वाहनों की विस्फोटक वृद्धि अक्सर बहुत अधिक भार और बिना चेतावनी संकेतों के, लापरवाह चालक गति के साथ पागल और उत्तेजक औषधि के साथ टिपसी, सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए यातायात नियमों का गैर-प्रवर्तन लेकिन व्यवस्थित भ्रष्टाचार के अवसर प्रदान करते हैं और बहुत कम और, एक संचयी प्रभाव के रूप में, बढ़ती राजमार्ग दुर्घटनाएं बिना किसी गलती के दायित्व और मुआवजे के दावों के मामलों में प्रक्रियात्मक गति और सरलता के माध्यम से अपकृत्य के कानून के लिए एक नए आयाम की मांग करती हैं। सामाजिक न्याय, राज्य द्वारा स्वयं सड़क मरम्मत की उपेक्षा करके, घातक अधिभार को नजरअंदाज करके और बस परिवहन के बड़े हिस्से और पूरे सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के बाद दायित्व को चुनौती देकर संविधान के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। मोटर दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का न्यायशास्त्र बिना किसी दोष के दायित्व की दिशा में विकसित होना चाहिए और मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए, न कि मामूली रूप से क्योंकि कानून एक स्वतंत्र देश में जीवन और अंगों को उदार पैमाने पर महत्व देता है। वर्तमान मामले में, मोटर साइकिल पर सवार एक डॉक्टर और उसके भाई को एक जीप चालक ने टक्कर मार दी और दोनों की मौत हो गई। यह घातक घटना नवंबर 1971 में हुई थी, लेकिन मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पांच साल बाद दावेदारों के दो समूहों को 80, 000/- और 73,500/- रुपये के लिए फैसला सुनाया।

ऐसे मामलों में पांच साल की देरी न्यायिक प्रक्रिया पर एक भयानक टिप्पणी है। यदि केवल नो-फॉल्ट देयता, पुलिस द्वारा स्वचालित रिपोर्टिंग जो दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित एक वैधानिक प्रो-फॉर्मा में दुर्घटना की जांच करती है और तमिलनाडु की तरह न्यायाधिकरण को भेजती है और प्रत्येक जिले में ऐसे न्यायाधिकरणों के विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण के साथ अनौपचारिक प्रक्रियाएं और अदालत-शुल्क से मुक्ति और

सबूत के बोझ के परिष्कृत नियम और सबूत के बोझ को पेश किया गया है-आसान और सस्ते यदि राज्य में उन गरीबों की मदद करने की इच्छा है जो ज्यादातर इस तरह की दुर्घटनाओं में मर जाते हैं-इस अनुकंपापूर्ण अधिकार क्षेत्र में कानून की देरी को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक न्याय राज्य की संवैधानिक संवेदनशीलता का पैमाना है। वैसे भी, हमने ये अवलोकन केंद्र और राज्यों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए किए हैं।

राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत द्वारा दोष और मात्रा दोनों पर दिए गए निष्कर्ष सही हैं। लेकिन उच्च न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया।

दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने आवश्यक गणना और कटौती करने के बाद 15 सितंबर, 1976 को अपना फैसला सुनाया। अपील 19 जनवरी, 1977 को या उससे पहले दायर की जानी थी, लेकिन वास्तव में 30 दिन बाद दायर की गई थी। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता के वकील ने सीमा की अवधि की गणना में गलती की है। उन्होंने तदनुसार पक्षों को सूचित किया था कि याचिकाकर्ता को देर से अपील करने के लिए गुमराह किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कानून के बारे में वकील की अज्ञानता देरी को माफ करने का कोई आधार नहीं है। रिलायंस को पंजाब उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर रखा गया था और ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 749 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का भी संदर्भ था। निष्कर्ष इन शब्दों में दिया गया थाः

"कंपनी अपीलार्थी का सहायक प्रभागीय प्रबंधक एक अनपढ़ या इतना अज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो सीमा की अवधि की गणना नहीं कर सकता है। इस तरह की अपीलें ऐसी कंपनियों द्वारा प्रतिदिन दायर की जाती हैं। इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जैसा कि पहले देखा गया है, कि गलती वास्तविक नहीं है और अपीलार्थी देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है।

हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते हैं। एक कंपनी अपने कानूनी सलाहकार पर निर्भर करती है और प्रबंधक की विशेषज्ञता कंपनी प्रबंधन में होती है न कि कानून में। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि जब कोई कंपनी या अन्य व्यक्ति कानूनी मामलों पर उसे या उसे सलाह देने के लिए एक वकील रखता है तो ऐसे वकील पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बेशक, अगर आम आदमी के लिए भी पेटेंट में बहुत देरी होती है या अगर समझ से बाहर उदासीनता है तो कानूनी राय की ढाल अभी भी कमजोर हो सकती है। ए. आई. आर. 1971 केर 211 में हममें से एक के फैसले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में सही कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई है:

"कानून यह तय करता है कि देरी को माफ करने में कुछ परिस्थितियों में वकील की गलती को ध्यान में रखा जा सकता है, हालांकि कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है कि वकील की गलती हमेशा एक पर्याप्त आधार होती है। यह हमेशा एक सवाल होता है कि क्या गलती वास्तविक थी या केवल एक गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था जैसे कि वादी की ओर से बाधाएं या एक गुप्त तरीके से सीमा को बचाने का प्रयास। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस मामले पर इस दृष्टिकोण से कभी विचार नहीं किया। यदि ऐसा होता, तो यह स्पष्ट रूप से देखा जाता कि सीमा अधिनियम से बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि स्थिति को गलत तरीके से पढ़ने के बावजूद इसका पालन किया गया था।"

"उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत मौजूदा अपीलों के विषय पर स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए 34 साल के अधिवक्ता होने के नाते श्री रायजादा संभवतः गलती नहीं कर सकते हैं और इसलिए, जिला न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की उनकी सलाह सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को पलट दिया।

"मेरा विचार है कि कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा दी गई कानूनी सलाह कभी-कभी गलत हो सकती है, भले ही अदालतों द्वारा कानून के प्रश्नों पर निर्णय कभी-कभी गलत हो। ऐसे मामलों में गलती करना मानवीय है और सामान्य लोग, जैसा कि वादी हैं, सलाह की पेशेवर क्षमता की जांच किए बिना, अन्य विभागों की तरह कानूनी रूप से विशेषज्ञ वकील पर निर्भर हो सकते हैं। अदालत को निश्चित रूप से यह देखना चाहिए कि क्या ऐसे मामलों में दुर्भावना का कोई दाग है या लापरवाही या चाल का कोई तत्व है। यदि दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो ईमानदारी से मांगी गई और वास्तव में दी गई कानूनी सलाह को सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन पर विचार किए जाने पर पर्याप्त कारण के रूप में माना जाना चाहिए। राज्य ने अपने कानूनी सलाहकारों पर भरोसा करने में अनुचित तरीके से काम नहीं किया है।"

हमने कंपनियों और सीमा की गणना के मामले में कानूनी राय पर भरोसा करने वाले अन्य व्यक्तियों की औचित्य और तर्कसंगतता के बारे में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर उत्पन्न हो सकती है। यदि कानूनी सलाहकार की राय को कंपनी के प्रबंधकों द्वारा अपनी खुद की कानूनी जांच के अधीन किया जाना है, तो एक असंभव स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में सरकार, जो

इस देश में एक बड़ी वादी है, मुश्किल में पड़ सकती है। यही कारण है कि हमने धारा 5 के आवेदन और वकील की गलती को इस विस्तार से समझाने का विकल्प चुना है।

यह अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में याचिकाकर्ता के लिए स्वतः वीजा सुरक्षित नहीं करता है। तथ्यात्मक निष्कर्षों में स्पष्ट अन्याय या घोर गलत सराहना या विकृति होनी चाहिए। हमने अभिलेख पर उपलब्ध सीमा तक मामले के गुण-दोष की जांच की है और याचिकाकर्ता के वकील को सुना है। उन्होंने शायद ही हमें आश्वस्त किया है कि मामले के गुण किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के लिए विवश हैं क्योंकि अब हमने खुद को या ऊपर बताए गए दोनों बिंदुओं को व्यक्त कर दिया है।

एस आर

याचिका निरस्त की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।